an>

Title: Need to provide subsidy on seeds, irrigation and solar energy equipment to farmers in Rajasthan.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : मैं किसानों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय माननीय कृषि मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। भारतीय कृषि मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करती है। मानसून समय पर नहीं आने एवं अल्पवृष्टि से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतिवृष्टि से बाढ़ आ जाती है। फसल पकने पर ओलावृष्टि एवं वर्षा से फसलें चौपट हो जाती है। राजस्थान का 2/3 भाग मरुस्थलीय एवं अर्द्ध मरुस्थलीय है तथा सम्पूर्ण राज्य में वर्षा कम होती है। यहां पर ड्रिप सिंचाई एवं सौर ऊर्जा से सिंगल फेज ट्यूबवैल चलाये जाते हैं। सौर ऊर्जा संयंत्रों में किसानों को अनुदान देने से पिछले कुछ वर्षों में किसान इनका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। नहरी क्षेत्र में खेतों में पक्की डिग्गी निर्माण पर जो अनुदान दिया जाता था, वह भी बन्द कर दिया गया है। इन विषम परिस्थितियों में किसान अपने परिवार एवं देश के लोगों का अनाज उत्पन्न कर पालन करता है। हमारी सरकार किसान हितैषी है एवं उनकी खुशहाली के लिए चिन्तित है। किसानों को संकट से उबरने के लिए एवं उसको बीज, खाद, सिंचाई उपकरण एवं सौर ऊर्जा उपकरणों आदि पर अनुदान दिया जाता रहा है। पिछले कुछ सालों से केन्द्र सरकार द्वारा ड्रिप सिंचाई उपकरण एवं सौर ऊर्जा उपकरणों आदि पर अनुदान दिया जाता रहा है लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा ड्रिप सिंचाई एवं सोलर सिस्टम पर अनुदान कम कर दिया गया है। अनुदान की राशि कम करने से किसानों में रोष व्याप्त है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः-

संयंत्र		सन् 2013-14 का देय अनुदान					सन् 2013-14 का देय अनुदान				
			प्रतिशत अंश					प्रतिशत अंश			
			केन्द्रीयांश	राज्यांश	अति राज्यांश	कृषक अंश		केन्द्रीयांश	राज्यांश	अति राज्यांश	कृषक अंश
	सामान्य	90	40	10	40	10	50	25	10	15	50
	लघु /सीमान्त	90	40	10	40	10	70	35	10	25	30
	डी.पी.ए.पी/ डी.डी.पी. क्षेत्र के सामान्य कृषक	90	40	10	40	10	70	35	10	25	30
	डी.पी.ए.पी./ डी.डी.पी. क्षेत्र के लघु सामान्य कृषक	90	40	10	40	10	70	50	10	10	30
सौलर पम्प	डी.पी.ए.पी./ डी.डी.पी. क्षेत्र के सामान्य कृषक	86	56	30	0	14	70	30	40	0	30
	डी.पी.ए.पी./ डी.डी.पी. क्षेत्र के लघु सामान्य कृषक	86	56	30	0	14	70	30	40	0	30

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूर्व की भाँति इन पर किसानों को अनुदान दिलाया जाए ताकि देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके।